कत्तिनोकुला मुराली कृष्णा

बनाम

वीरमल्ल कोटेश्वर राव और अन्य

(सिविल अपील सं. 7701/ 2009)

23 नवंबर, 2009

[डी. के. जैन और आर. एम. लोधा, जे. जे.]

चुनाव कानूनः

मतों की पुनः गिनती- पंचायत चुनाव- आयोजितःचूंकि मतपत्रों के निरीक्षण और पुनः गणना का आदेश मतपत्र की गोपनीयता को प्रभावित करता है, इसलिए इस तरह का आदेश निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं दिया जा खंडता है- मतों की फिर से गिनती के लिए आवश्यकताएं- समझाया गया- चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने भी मतों की फिर से गिनती की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय लागू किए जाने वाले मापदंडों की दृष्टि खो दी- पूर्वाग्रह का सिद्धांत फिर से गिनती का आदेश देने के लिए एक अप्रासंगिक कारक है- इसी तरह, लौटे उम्मीदवार और चुनाव याचिकाकर्ता के बीच मतों का संकीर्ण अंतर इस धारणा को जन्म नहीं देता है कि मतों की गिनती में अनियमितता या अवैधता हुई थी- चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुनर्मतगणना का

आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, रद्द कर दिया गया- आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994- एस. 233

चुनाव याचिका- भौतिक तथ्य- रखा गयाःचुनाव याचिका में स्पष्ट रूप से बताना होगा और फिर ठोस रूप से साबित करना होगा।

सबूत- तत्काल मामले में, यहां तक कि बुनियादी भौतिक तथ्य जो चुनाव न्यायाधिकरण को प्रथमदृष्टया संतुष्टि दर्ज करा खंडते थे कि मतपत्र की फिर से गिनती आवश्यक थी, याचिका में गायब थे।

प्रमाणः

चुनाव याचिका- चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता, अनुचितता या अवैधता के आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी- अभिनिर्धारित:

चुनाव याचिकाकर्ता पर है और चुनाव अधिकारी- चुनाव कानून पर नहीं है।

शब्द और छंदः

अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य'- चुनाव कानून के संदर्भ में इसका अर्थ। उत्तरदाता नं. 1 ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 233 के तहत एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच के पद के लिए अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती दी गई, मुख्य रूप से अवैधता के आधार पर मतों की गिनती और उखंडे पक्ष में पड़े मतों की अस्वीकृति को अमान्य बताया गया। हालांकि चुनाव न्यायाधिकरण ने

दोनों भौतिक मुद्दों को लौटे उम्मीदवार के पक्ष में पाया, फिर भी वोटों की फिर से गिनती का आदेश दिया, क्योंकि उसकी राय में, यह लौटे उम्मीदवार के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि की। परेशान होकर, लौटे उम्मीदवार ने अपील दायर की।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. चुनाव कानून में निर्धारित हितकारी सिद्धांत यह है कि चूंकि मतपत्रों के निरीक्षण और पुनः गिनती का आदेश मतपत्र की गोपनीयता को प्रभावित करता है, इसलिए इस तरह का आदेश निश्चित रूप से नहीं किया जा खंडता है। निस्संदेह, पूरी चुनाव प्रक्रिया में, मतपत्र की गोपनीयता पवित्र और अलंघनीय है, सिवाय इखंडे कि जहां मतों की गिनती में शुद्धता, औचित्य और वैधता पर संदेह करने के लिए मजबूत प्रथमदृष्टया परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं। यह कहना सरल होगा कि इससे पहले कि चुनाव न्यायाधिकरण मतपत्रों की जांच की अनुमति दे और फिर से गिनती का आदेश दे, दो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात् ((i) निर्वाचन याचिका- मतपत्रों की पुनः गणना की मांग करने वाली याचिका में उन सभी भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण होना चाहिए, जिनके आधार पर गणना में अनियमितता या अवैधता के आरोप स्थापित किए गए हैं, और (ii) आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, न्यायाधिकरण को, प्रथमतः, होना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद का निर्णय करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्यायाधीश के लिए इस तरह का आदेश देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। [पैरा11] [1073- ए- सी]

सुरेश प्रसाद यादव अन्य जय प्रकाश मिश्रा और अन्य- (1975) 4 एससीसी 822; पी. के. के. शम्सुद्दीन अन्य के. ए. एम. मप्पिल्लई मोहिंदीन और अन्य। (1989) 1 एस. सी. सी. 526; वादिवेलु अन्य सुंदरम और अन्य। (2000) 8 एस. सी. सी. 355, महेंद्र पाल अन्य राम दास मा/क्रोध और अन्य। (2002) 3 खंड. 457 आई. एम. चिफिनासामी अन्य के. सी. पलानीसामी और अन्य। (2004) 6 एस. सी. सी. 341, बलदेव सिंह अन्य शिंदर पाल सिंह और अन्र। (2007) 1 एस. सी. सी. 341 और पोथुला रामा राव अन्य पेंड्याला वी. एफ.) नाकाटा कृष्ण राव और अन्य। (2007)

11 खंड 1, पर भरोसा किया।

1.2. मोटे तौर पर, भौतिक तथ्य प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जिन्हें चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपनी वाद हेतुक कारण को साबित करने के लिए और प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव को साबित करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। लेकिन, जिसे भौतिक तथ्य कहा जा खंडता है, वह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक

अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा खंडता है। [पैरा 11] [10731- 3 सी.- डी]

1.3. तत्काल मामले में, चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने मतों की फिर से गिनती की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय लागू किए जाने वाले मापदंडों की दृष्टि खो दी। चुनाव याचिका के पैराग्राफ 4 से, जिसमें चुनौती के आधार हैं, यह स्पष्ट है कि मतों की गिनती में अनियमितता या अवैधता के आरोप न केवल अस्पष्ट थे, बल्कि बुनियादी भौतिक तथ्य भी थे जो चुनाव न्यायाधिकरण को एक प्रथमदृष्टया संतुष्टि दर्ज कर खंडते थे कि मतपत्रों की फिर से गिनती आवश्यक थी, याचिका में गायब थे। यह ध्यान दें योग्य है कि दलों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर, चुनाव न्यायाधिकरण ने स्वयं कहा था कि चुनाव याचिकाकर्ता मतों की अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करने में चुनाव अधिकारी की विफलता के बारे में कोई ठोस तथ्य बताने में विफल रहा है और आगे इस बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं था कि किस मेज पर चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों को अपीलार्थी के पक्ष में डाले गए मतों के साथ मिलाया गया था; और किस मेज पर उखंडे पक्ष में डाले गए मतों को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया गया था। सटीक रूप से इस कारण से, चुनाव न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने से इनकार कर दिया था। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनों से परे साक्ष्य

को न तो प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा खंडती है और न ही ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखा जा खंडता है। [पैरा 15] [1076- डी- एच; 1077- ए]

1.4. चुनाव न्यायाधिकरण की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि एक आदेश को फिर से गिनने के लिए एकमात्र कारक यह था कि यदि मतपत्रों की फिर से गिनती की जाती है तो अपीलकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसी तरह, चुनाव न्यायाधिकरण के विचार की पुष्टि करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ जिस कारक का विचार किया गया, वह यह है कि मतों की फिर से गिनती से चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, विशेष रूप से जब मतों का अंतर बहुत कम था। इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि पुनर्मतगणना के निर्देश से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, जो मतपत्र की गोपनीयता का भी भंग कर खंडते हैं, पूर्वाग्रह का सिद्धांत आदेश देने के लिए एक अप्रासंगिक कारक है, लौटे उम्मीदवार और चुनाव याचिकाकर्ता के बीच मतों का एक संकीर्ण अंतर स्वयं इस धारणा को जन्म नहीं देता है कि मतों की गिनती में अनियमितता या अवैधता हुई थी। [पैरा 15] [1077- 8- E]

2.1. सबसे पहले, चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताना होगा और फिर ठोस साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा। निस्संदेह, चुनाव अधिकारी की ओर से चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता, अनुचितता या अवैध रूप से आरोप साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव याचिकाकर्ता पर है,

न कि चुनाव अधिकारी पर, जैसा कि नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा माना गया है। तत्काल मामले में, नीचे दिए गए दोनों मंचों ने पाया है कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों की कमी थी। ऐसा मानने के बाद, चुनाव याचिका को केवल इसी अल्प आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। मामले के उस दृष्टिकोण में, चुनाव न्यायाधिकरण की टिप्पणी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, कि चुनाव अधिकारी फॉर्म 26 में सुधार और ओवर- राइटिंग के बारे में कुछ भी कहने में विफल रहे हैं, न तो तथ्यात्मक रूप से सही है और न ही कानूनी रूप से। [पैरा 15] [1077- ई- जी]

2.2. अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिखंडे आधार पर चुनाव न्यायाधिकरण एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच खंडता था कि मतपत्रों की फिर से गिनती का आदेश देने का मामला बनाया गया था। चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुनः गिनती का आदेश अवैध था और उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखने में गलती की। चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 16 और 17]

मामला कानून संदर्भःए.

(2000) एक खंड 355 पैरा 9 पर निर्भर था।

(2002) 3 धारा 457 पैरा 9 पर निर्भर थी।

(2004) धारा 341 पैरा 9 पर निर्भर थी।

(2007) 1 धारा 341 पैरा 9 पर निर्भर।

(2001) 11 खंड 1 पैरा- 9- बी पर निर्भर।

(1975) 4 खंड एस 22 पैरा 12 पर निर्भर था।

(1989) 1 धारा 526 पैरा 13 पर निर्भर थी।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7701/2009

हैदराबाद उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के 2007 सी. आर. पी. सं. 3955 में दिनांकित 27.09.2007 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए सी. मुकुंद, शशांक शर्मा, अवनीश गर्ग, वंदना आनंद, मीरा माथुर, बिजय कुमार जैन।

सीबीएन बाबू, रेणु त्यागी, रामेश्वर ने गोयल को "प्रतिवादीओं" के लिए प्रेरित किया।

न्यायालय का निर्णय डी. के. जैन, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अवकाश अनुदत्त गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में चुनौती हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 27 सितंबर, 2007 के फैसले और आदेश को दी गई है। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने 10

अगस्त, 2007 के आदेश की पुष्टि की है, जिसे प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोवुर, (जिसे इखंडे बाद "चुनाव न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 2006 के ई. ओ. पी. संख्या 7 में पारित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव में डाले गए मतों की फिर से गिनती का आदेश दिया गया है।

3. खंड्षेप में, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले भौतिक तथ्य इस प्रकार हैं:

आंध्र प्रदेश राज्य में पश्चिम गोदावरी जिले के निदादवोले मंडल के रविमेटला गाँव की ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव 2 अगस्त, 2006 को हुआ था। अपीलकर्ता, प्रथम प्रत्यर्थी (इखंडे बाद "चुनाव याचिकाकर्ता" के रूप में संदर्भित), और दो अन्य लोगों ने चुनाव लड़ा। मतों की गिनती के बाद, अपीलकर्ता को 552 मत मिले और निकटतम प्रतिद्वंद्वी, चुनाव- याचिकाकर्ता को 550 मत मिले। 67 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। चुनाव याचिकाकर्ता ने इस अपील में चुनाव अधिकारी, प्रतिवादी संख्या ए से मतों की फिर से गिनती के लिए अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। पुनः गणना में, अमान्य मतों की संख्या घटाकर 65 कर दी गई क्योंकि 2 मत वैध पाए गए, जिनमें से प्रत्येक ने अपीलकर्ता और चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार, अपीलकर्ता और चुनाव याचिकाकर्ता के बीच

मतों का अंतर 2 मतों का बना रहा। तदनुसार, अपीलकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया।

4. चुनाव परिणाम से असंतुष्ट होकर, चुनाव याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की खंड 233 के तहत चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की। चुनाव याचिका का पैराग्राफ 4, जिसमें परिणाम को चुनौती देने के आधार हैं, वर्णनात्मक रूप में है और इसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "पाँचवाँ प्रतिवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन (एस. आई. सी. समर्थक) है। चुनाव अधिकारियों, तीसरे प्रतिवादी और पुलिस को प्रबंधित किया गया है और कई भ्रष्ट आचरण किए गए हैं। चुनावों की गिनती, मतों की अस्वीकृति और मतों को जोड़ना, संपत्ति (एस. आई. सी. ठीक से) नहीं थी। याचिकाकर्ता के 50 से अधिक मतों को अमान्य बताते हुए गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। बावजूद याचिकाकर्ता और उखंडे एजेंटों ने इसका कड़ा विरोध किया। याचिकाकर्ता के मतों को गलत तरीके से गिना गया और 5वें प्रतिवादी के बंडलों में डाला गया। यदि उपरोक्त अवैधताएं और अनियमितताएं नहीं होतीं, तो याचिकाकर्ता को वोट मिलते और पांचवें प्रतिवादी को केवल 498 वोट

मिलते। उपरोक्त अवैधताओं और भ्रष्ट प्रथाओं के कारण, चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ और 5वें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को रविमेटला ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए निर्वाचित घोषित करने के बजाय गलत तरीके से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने तीसरे प्रतिवादी के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया जिसमें उनसे वोटों की फिर से गिनती करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उसे 2.8.2006 पर अस्वीकार कर दिया गया था। कोई समर्थन नहीं दिया गया था। "

5. चुनाव याचिका को अपीलकर्ता ने इस आरोप को नकारते हुए चुनौती दी थी कि चुनाव अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया था। पुनः गणना की मांग, यह कहा गया था कि वास्तव में, चुनाव याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंटों द्वारा दो लिखित अभ्यावेदन किए गए थे और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। दो बार फिर से गिनती के बाद, रिपोर्ट को फॉर्म सं॰25 (sic 26) में खंडलित किया गया और निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। दलों की दलीलों पर, चुनाव न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

"1.क्या तीसरे उत्तरदाता 8 द्वारा मतों की गिनती नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं थी?

2. क्या याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया गया था और क्या याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों को पांचवें प्रतिवादी के पक्ष में डाले गए मतों में मिलाया गया था?

3. क्या याचिकाकर्ता अस्वीकृत मतों सहित मतों की पुनः गिनती की राहत का हकदार है?

4. क्या याचिकाकर्ता इस घोषणा की राहत का हकदार है कि 5वें प्रतिवादी के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना है?

5. यदि हां, तो क्या याचिकाकर्ता यह घोषणा करने का हकदार है कि वह रविमेटला ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में विधिवत निर्वाचित हुआ है?

6. किस राहत के लिए?"

6. पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से, स्वयं चुनाव याचिकाकर्ता सहित पाँच गवाहों से पूछताछ की गई और कुछ दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। अपीलकर्ता ने अपने (आर. डब्ल्यू. 2) और चुनाव अधिकारी (आर. डब्ल्यू. 1) सहित चार गवाहों से पूछताछ की। उम्मीदवारों के एफ के पक्ष में मतदान की प्रक्रिया के सारांश

के संबंध में फॉर्म सं. 26 को भी (Ex.81) के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

7. साक्ष्य पर विचार करने पर, चुनाव न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चुनाव याचिकाकर्ता कोई विशिष्ट आरोप लगाने में विफल रहा है कि किस मेज पर उखंडे पक्ष में पड़े मतों को अपीलकर्ता के पक्ष में पड़े मतों के साथ मिलाया गया था और किस मेज पर उखंडे पक्ष में पड़े मतों को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया गया था। चुनाव न्यायाधिकरण ने यह भी नोट किया कि चुनाव याचिका में चुनाव याचिकाकर्ता ने वोट को अस्वीकार करने के कारण का उल्लेख करने में चुनाव अधिकारी की विफलता के बारे में कोई भौतिक तथ्य नहीं बताए थे, और इसलिए, इस संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता के नेतृत्व में साक्ष्य, दलीलों से परे होने के कारण, उन पर भरोसा नहीं किया जा खंडता था। चुनाव न्यायाधिकरण ने चुनाव याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आंध्र प्रदेश पंचायत राज (चुनाव संचालन) नियम, 1994 के नियम 34 (4) का पालन नहीं किया गया था, जिसमें प्रत्येक अस्वीकृत मतपत्र पर चुनाव अधिकारी द्वारा "अस्वीकृत" शब्द का समर्थन करने का प्रावधान है, और इस प्रकार उस कारण से चुनाव परिणाम दूषित नहीं किया गया था। निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रपत्र सं॰26 (Ex.81) में पुनर्लेखन और सुधार के आरोप के संबंध में, वर्तमान उद्देश्य के लिए सामग्री, निर्वाचन न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

"अभिलेख पर उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, भले ही याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में उक्त भौतिक तथ्य को दरकिनार नहीं किया कि चुनाव अधिकारी ने प्रपत्र सं॰26 में कई सुधार या अधिक लेखन किए थे और इस तरह चुनाव परिणाम दूषित हो जाता है, और न ही पूर्व में किए गए उक्त सुधारों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। बी 1 भले ही ईएक्स बी 1 इस न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रतिवादी के काउंटर के साथ दायर किया गया था। मेरी यह सुविचारित राय है कि तीसरे प्रत्यर्थी आर. डब्ल्यू. 1 पर इस न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने का भारी बोझ था कि उन सुधारों के कारणों के बारे में और उन पर उनके द्वारा पूर्व में क्यों लिखा गया है। 1. लेकिन आश्चर्यजनक रूप से न तो तीसरे प्रतिवादी द्वारा दायर काउंटर में और न ही आर. डब्ल्यू. 1 के मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में उन्होंने उक्त सुधारों और ईएक्स बी 1 में उनके द्वारा किए गए लेखन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि आर. डब्ल्यू. 1 ने उक्त सुधारों के संबंध में और ईएक्स बी 1 पर दिखाई देने वाले लेखन के बारे में बिल्कुल भी प्रतिपरीक्षा नहीं की थी, लेकिन आर. डब्ल्यू. 2 से 4 की प्रतिपरीक्षा की गई थी,

उक्त सुधारों के संबंध में और इसमें किए गए लेखन के बारे में। ईएक्स बी 1"।

इस प्रकार, यद्‌यपि निर्वाचन न्यायाधिकरण ने नोट किया कि उक्त प्रपत्र में सुधार और अधिलेखन के संबंध में निर्वाचन याचिका में कोई कथन नहीं था और न ही इस संबंध में निर्वाचन याचिकाकर्ता द्‌वारा कोई ठोस साक्ष्य दिया गया था, फिर भी यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्वाचन अधिकारी न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे थे ताकि यह इंगित किया जा खंडे कि वे सुधार और अधिलेखन प्रपत्र सं॰26 में क्यों किए गए थे। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और सभी मतों की पुनः गिनती चुनाव याचिकाकर्ता और अपीलकर्ता सहित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्‌वारा डाले गए मतों की संख्या का पुनर्निर्धारण करेगी, इसलिए यह मतपत्रों की पुनः गिनती के लिए एक उपयुक्त मामला था। चुनाव न्यायाधिकरण ने चुनाव याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्‌दों संख्या 1 और 2 का जवाब दिया और चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में और अपीलकर्ता के खिलाफ संख्या 3 जारी किया। 8 नंबर 4 से 6 तक के मुद्‌दों के संबंध में, चुनाव न्यायाधिकरण ने कहा कि वोटों की फिर से गिनती पूरी होने के बाद ही इनका जवाब दिया जाएगा।

8. मतपत्रों की पुनः गिनती के निर्देश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष नागरिक संशोधन याचिका को प्राथमिकता दी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हालांकि यह सच है कि मतों की फिर से गिनती का सहारा नहीं लिया जा खंडता है और मतपत्रों की गोपनीयता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में उल्लिखित आंकड़ों की वास्तविकता और शुद्धता के बारे में संदेह को नजरअंदाज नहीं किया जा खंडता है, जैसे कि फॉर्म सं॰26, विशेष रूप से जब सफल और असफल उम्मीदवारों के बीच अंतर कम हो। दो वोट; पुनर्मतगणना में, दो वोट, जिन्हें शुरू में अमान्य घोषित किया गया था, को वैध माना गया और यदि उन्हें चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में गिना जाता, तो परिणाम पूरी तरह से झुक जाता। यह देखते हुए कि केवल मतों की पुनः गिनती के कारण, अपीलकर्ता को किसी भी कठिनाई में नहीं डाला जाएगा, बल्कि यह प्रक्रिया में पारदर्शिता को मजबूत करेगा, उच्च न्यायालय ने चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश की पुष्टि की और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

9. निर्वाचन न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णय पर जोर देते हुए, अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सी. मुकुंद ने पुरजोर आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए मतपत्रों की फिर से गिनती का निर्देश देते हुए कानून की गंभीर त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता के पक्ष में दो भौतिक मुद्दों, यानी मुद्दे संख्या 1 और 2 का निर्णय लेने के बाद, नीचे दिए गए अधिकारियों को केवल आधार पर मतों की फिर से गिनती का निर्देश देना उचित नहीं था।

पुनः गणना के ऐसे आदेश से किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह या कठिनाई नहीं होगी। यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर अवैधता की कि चुनाव अधिकारी यह दिखाने में विफल रहे कि उनके द्वारा फॉर्म No.26 में सुधार और ओवर-राइटिंग क्यों की गई, जबकि चुनाव याचिका में इस संबंध में कोई ठोस तथ्य नहीं बताए गए थे और यहां तक कि आरोप साबित करने की जिम्मेदारी भी चुनाव याचिकाकर्ता पर थी। विद्वान अधिवक्ता वादिव/यू अन्य सुंदरम और अन्य1, महेंद्र पाल अन्य राम दास मा/क्रोध और अन्य2, एम. चिन्नासामी अन्य के. सी. में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। पलानीसामी और ओआरएस। 3, बलदेव सिंह अन्य शिंदर पाल सिंह और

अन्न। 4 और पोथुला रामा राव अन्य पेंड्याला वेन उर्फ ता कृष्ण राव और अन्य।

10. दूसरी ओर, चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सी. बी. एन. बाबू ने चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव द्वारा पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई थी। याचिकाकर्ता, जिखंडे आधार पर चुनाव न्यायाधिकरण ने अपनी संतुष्टि को सही ढंग से दर्ज किया था कि फिर से गिनती के लिए एक मामला था बनाया गया है।

11. दलों की ओर से उठाए गए मुद्दों के गुण-दोष की जांच करने से पहले, चुनाव कानून में निर्धारित हितकारी सिद्धांत को ध्यान में रखना उचित होगा कि चूंकि मतपत्रों के निरीक्षण और पुनः गिनती का आदेश मतपत्र की गोपनीयता को प्रभावित करता है, इसलिए ऐसा आदेश निश्चित रूप से नहीं किया जा खंडता है। निस्संदेह, पूरी चुनाव प्रक्रिया में, मतपत्र की गोपनीयता पवित्र और अलंघनीय है, सिवाय इखंडे कि जहां मतों की गिनती में शुद्धता, औचित्य और वैधता पर संदेह करने के लिए मजबूत प्रथमदृष्टया परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं। महत्व। मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने और उन परिस्थितियों पर विचार किया गया है जिनके तहत उस गोपनीयता का उल्लंघन किया जा खंडता है।

1. (2000) 1 खंडंड 355

2. (2002) 3 धारा 457

3. (2004) 1 धारा 341

4. (2007) 1 धारा 341

5. (2007) 11 खंड 1

यह न्यायालय कई मामलों में। यह कहना आसान होगा कि ए. जे. से पहले एक चुनाव न्यायाधिकरण मतपत्रों की जांच की अनुमति दे खंडता है और फिर से गिनती का आदेश दे खंडता है, दो बुनियादी आवश्यकताएं अर्थात (i) मतपत्रों की फिर से गिनती की मांग करने वाली चुनाव याचिका में पर्याप्त होना चाहिए।

उन सभी भौतिक तथ्यों का विवरण जिनके आधार पर गणना में अनियमितता या अवैधता के आरोप स्थापित किए गए हैं, और (ii) आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, न्यायाधीशाधिकरण को, प्रथमदृष्टया, संतुष्ट होना चाहिए कि विवाद का निर्णय करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्यायाधीश करने के लिए, ऐसा आदेश देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मोटे तौर पर, भौतिक तथ्य प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जिन्हें चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपनी वाद हेतुक कारण को साबित करने के लिए और प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव को साबित करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। लेकिन, जिसे भौतिक तथ्य कहा जा

खंडता है, वह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा खंडता है।

12. सुरेश प्रसाद यादव बनाम जय प्रकाश मिश्रा और _.Ors मामले में, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर मतपत्रों के निरीक्षण और/या पुनः गिनती के लिए अनुरोध करने में निर्धारित सिद्धांतों का सारांश देते हुए, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उन परिस्थितियों का खंडेत दिया जिसमें इस तरह के अनुरोध पर विचार किया जा खंडता है। पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति सरकारिया ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः(एससीसी पृष्ठ 824-825) E

> ".. इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि मतपत्रों के निरीक्षण और पुनः गिनती का आदेश पाठ्यक्रम के रूप में नहीं किया जा खंडता है। इसका कारण दो गुना है। सबसे पहले इस तरह का आदेश मतपत्र की गोपनीयता को प्रभावित करता है जिसे कानून के तहत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा, नियम मतपत्रों की गिनती के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में इतनी सारी वैधानिक जाँच और गलतियों और गिनती में धोखाधड़ी के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय शामिल हैं, कि इसे लगभग चालबाजी फूलप्रूफ कहा जा खंडता है। हालाँकि कोई कठोर

और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा खंडता है, फिर भी व्यापक दिशानिर्देश, जो इस न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट हैं, इस प्रकार इंगित किए जा खंडते हैं: न्यायालय को मतपत्रों की पुनः गिनती का आदेश केवल वहाँ देना उचित होगा जहाँ:

(1) चुनाव-याचिका में उन सभी भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण होता है जिन पर गिनती में अनियमितता या अवैधता के आरोप लगाए जाते हैं।

(2) प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसे आरोप प्रथमदृष्टया स्थापित होते हैं, जो यह विश्वास करने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं कि गिनती में गलती हुई है; और

(3) याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत प्रथमदृष्टया संतुष्ट है कि विवाद का फैसला करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्यायाधीश करने के लिए इस तरह का आदेश देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।"

13. पी. के. के. शम्सुद्दीन अन्य के. ए. एम. मप्पिल्लई मोहिंदीन और अन्य 7, याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में एक पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव में, पहले प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित किया गया और याचिकाकर्ता ने चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी कि गिनती

के दौरान, निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए कुछ वैध मतों को गलत तरीके से अमान्य मत माना था और कुछ अमान्य मतों को वैध मतों के रूप में माना गया था जो पहले प्रतिवादी के पक्ष में डाले गए थे और निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के एजेंट को गिनती के समय मतपत्रों की जांच करने की अनुमति नहीं दी थी। न्यायाधिकरण ने सभी उम्मीदवारों और सहायक निर्वाचन अधिकारी के साक्ष्य दर्ज करने के बाद मतों की फिर से गिनती का आदेश दिया। मतों की फिर से गिनती करने पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त मतों की संख्या में कोई अंतर नहीं था, लेकिन जहां तक पहले प्रतिवादी का संबंध था, उन्होंने केवल 528 मत प्राप्त किए थे, जबकि मूल रूप से उन्हें 649 मत प्राप्त हुए थे। 121 उनके पक्ष में डाले गए वोट अमान्य पाए गए थे। पुनर्मूल्यांकन के आंकड़ों के आधार पर, चुनाव याचिकाकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था क्योंकि उसने पुनर्मूल्यांकन पर पहले प्रतिवादी की तुलना में 28 वोट अधिक प्राप्त किए थे। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका में पहले प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि न्यायाधिकरण ने मतों की फिर से गिनती का आदेश देने में गलती की थी, जबकि याचिकाकर्ता ने डाले गए मतों की फिर से गिनती के आदेश के लिए प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनाया था। इस आदेश को इस अदालत में चुनौती दी गई थी। उच्च

न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को कायम रखते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः(एस. सी. सी. पी. 531)

"13. इस प्रकार कानून की स्थिर स्थिति यह है कि मतपत्रों की जांच और मतों की फिर से गिनती के आदेश का औचित्य पीछे हटकर और मतों की फिर से गिनती के परिणाम से प्राप्त नहीं किया जाना है। इखंडे विपरीत, मतों की पुनः गिनती के आदेश के लिए औचित्य एक चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा सीमा पर रखी गई सामग्री द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वास्तव में मतों की पुनः गिनती का आदेश दिया जाए। इस हितकारी नियम का कारण यह है कि मतपत्र की गोपनीयता का संरक्षण एक पवित्र सिद्धांत है जिसे हल्के में या जल्दबाजी में तब तक नहीं तोड़ा जा खंडता जब तक कि इसकी प्रथमदृष्टया वास्तविक आवश्यकता न हो। चुनाव परिणाम की वैधता पर हमला करने और मतों की फिर से गिनती की मांग करने के लिए एक पराजित उम्मीदवार का अधिकार इस मूल सिद्धांत के अधीन होना चाहिए कि लोकतंत्र में मतपत्र की गोपनीयता पवित्र है और इसलिए जब तक प्रभावित उम्मीदवार सबूत के माध्यम से स्वीकार्य उपाय में आरोप और पुष्टि नहीं करता है कि न्यायाधीश के हित में चुनाव

न्यायाधीशाधिकरण द्वारा आदेश दिए जा रहे मतों की फिर से गिनती के लिए उच्च स्तर की संभावना का एक प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है, एक न्यायाधीशाधिकरण या अदालत को मतों की फिर से गिनती का आदेश नहीं देना चाहिए। (हमारे द्वारा दिया गया जोर)"

14. तमिलनाडु में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित वादिवेलु के मामले (उपरोक्त) में फिर से मतदान और गिनती में विभिन्न अनियमितताओं के आधार पर परिणाम को चुनौती दी गई। जीतने वाले उम्मीदवार और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्राप्त मतों का अंतर केवल एक वोट था। चुनाव न्यायाधिकरण ने हारने वाले उम्मीदवार की चुनाव याचिका को मंजूरी दे दी और फिर से गिनती का आदेश दिया गया। नतीजतन, चुनाव याचिकाकर्ता को 1002 वोट मिले और निर्वाचित उम्मीदवार को केवल 975 वोट मिले। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुनः गणना का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं थे और पुनः गणना के लिए प्रथमदृष्टया मामला नहीं था। इस प्रकार, चुनाव याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने के. जी. बालकृष्णन, जे. (उस समय उनके प्रभु के रूप में) द्वारा से बोलते हुए इस प्रकार खुलासा कियाः

"मतों की पुनः गिनती का आदेश बहुत कम दिया जा खंडता था और चुनाव याचिका में अभिवचनों में विशिष्ट आरोप पर कि गिनती के दौरान अवैधता या अनियमितता की गई थी। पुनः गिनती की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को आरोप लगाना चाहिए और यह साबित करना कि अमान्य मतों की अनुचित स्वीकृति या वैध मतों की अनुचित अस्वीकृति थी। यदि केवल अदालत उपरोक्त आरोप की सच्चाई के बारे में संतुष्ट है, तो वह वोटों की फिर से गिनती का आदेश दे खंडती है। चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतपत्र की गोपनीयता को हमेशा पवित्र माना गया है और गिनती में अवैधता या अनियमितता के आरोपों से इसे हल्के में नहीं लिया जा खंडता है। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि चुनावों की शुद्धता को धूमिल किया गया है और इसने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है जिससे हार गए हैं। उम्मीदवार गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, अदालत पार्टियों के बीच न्यायाधीश करने के लिए ऐसी परिस्थितियों में वोटों की फिर से गिनती का सहारा ले खंडती है। (जोर दिया गया)"

15. ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में मामले को देखने के बाद, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च

न्यायालय ने मतों की फिर से गिनती की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय लागू किए जाने वाले मापदंडों की दृष्टि खो दी है। यह चुनाव याचिका के पूर्व-निकाले गए पैराग्राफ 4 से स्पष्ट है, जिसमें चुनौती के आधार हैं, मतों की गिनती में अनियमितता या अवैधता के बारे में आरोप न केवल अस्पष्ट थे, बल्कि बुनियादी भौतिक तथ्य भी थे जो चुनाव न्यायाधिकरण को एक प्रथमदृष्टया संतुष्टि दर्ज कर खंडते थे कि मतपत्रों की फिर से गिनती आवश्यक थी, याचिका में गायब थे। यह ध्यान दें योग्य है कि दलों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर, निर्वाचन न्यायाधिकरण ने स्वयं कहा था कि निर्वाचन याचिकाकर्ता मतों की अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करने में निर्वाचन अधिकारी की विफलता के बारे में कोई ठोस तथ्य बताने में विफल रहा है और इखंडे अलावा इस बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं था कि किस मेज पर निर्वाचन याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों को अपीलार्थी के पक्ष में डाले गए मतों के साथ मिलाया गया था और किस मेज पर उखंडे पक्ष में डाले गए मतों को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया गया था। सटीक रूप से इस कारण से, और हमारे विचार में सही, चुनाव न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने से इनकार कर दिया था। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनों से परे साक्ष्य को न तो प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा खंडती है और न ही ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखा जा खंडता है। इखंडे अलावा, यहां तक कि दो

भौतिक मुद्दे, जैसे कि क्या चुनाव अधिकारी द्वारा मतों की गिनती नियमों और विनियमों के अनुसार थी और यह भी कि क्या चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतों को अमान्य के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था या अनुचित था. अपीलकर्ता के पक्ष में मतों का मिश्रण पाया गया है।उपरोक्त पैरा 7 में निकाले गए निर्वाचन की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि पुनः गणना का आदेश देने के लिए एकमात्र कारक यह था कि यदि मतपत्रों की पुनः गणना की जाती है तो अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह, चुनाव न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ जिस कारक का वजन था, वह यह है कि वोटों की फिर से गिनती चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता को मजबूत करेगी, खाखंडर जब वोटों का अंतर बहुत कम था। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि पुनः गिनती के निर्देश से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, जो मतपत्र की गोपनीयता का भंग भी कर खंडते हैं, पूर्वाग्रह का सिद्धांत पुनः गिनती का आदेश देने के लिए एक अप्रासंगिक कारक है। इसी तरह, निर्वाचित उम्मीदवार और चुनाव याचिकाकर्ता के बीच मतों का एक छोटा अंतर इस धारणा को जन्म नहीं देता है कि मतों की गिनती में अनियमितता या अवैधता हुई थी। सबसे पहले, इस संबंध में भौतिक तथ्यों को चुनाव याचिकाकर्ता में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और फिर ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, चुनाव अधिकारी की ओर से

चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता, अनुचितता या अवैधता के आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव याचिकाकर्ता पर है, न कि चुनाव अधिकारी पर, जैसा कि नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा माना गया है। वर्तमान मामले में, नीचे दिए गए दोनों मंचों ने पाया है कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों की कमी थी। ऐसा मानने के बाद, हमारे विचार में, चुनाव याचिका को केवल इसी छोटे आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। मामले के उस दृष्टिकोण में, चुनाव न्यायाधिकरण की टिप्पणी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, कि चुनाव अधिकारी फॉर्म 26 में सुधार और अति-लेखन के बारे में कुछ भी कहने में विफल रहे हैं, न तो तथ्यात्मक रूप से सही है और न ही कानूनी रूप से।

16. हमारी राय है कि पूर्व-उल्लिखित तथ्यात्मक परिदृश्य और इस तथ्य के आलोक में कि मुद्दों संख्या 1 और 2 पर चुनाव न्यायाधिकरण के निष्कर्ष अपीलकर्ता के पक्ष में थे, एक गंजे याचिका को छोड़कर कि गिनती में कुछ अनियमितताएं और अवैधताएं की गई थीं, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिखंडे आधार पर चुनाव न्यायाधिकरण एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच खंडता था कि मतपत्रों की फिर से गिनती का आदेश देने का मामला बनाया गया था। इन सभी कारणों से, हम आश्वस्त हैं कि चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुनः गिनती का आदेश अवैध था और उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखने में गलती की।

17. पूर्व में चल रही चर्चा को देखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है; चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा मतपत्रों की फिर से गिनती का आदेश देते हुए पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलकर्ता लागतों का हकदार होगा, जिसकी मात्रा Rs.20,000/- होगी।

आर. पी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंजलि सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।